भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2310

जिसका उत्तर 7 अगस्त, 2026 को दिया जाना है ।

16 श्रावण, 1948 (शक)

डिजिटल इंडिया मिशन की उपलब्धियां

2310. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल इंडिया मिशन की अब तक क्या उपलब्धियां रहीं हैं;
(ख) इंटरनेट उपयोगकर्ता एवं डिजिटल भुगतानों की वार्षिक वृद्धि दर क्या है; और
(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसके मूल में, यह कार्यक्रम तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर और एपीआई सेतु) आदि के लिए जनसंख्या पैमाने पर मूलभूत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को सफलतापूर्वक लागू किया है। डीपीआई भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी शक्ति रही है, जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन, शासन और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है।

डिजिटल इंडिया पहल मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ है, जिसने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन में सुधार और समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआई का विस्तार करना भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है, जिससे ग्रामीण और कमजोर आबादी को अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकारी सेवाओं तक समावेशी और समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:

डिजिटल कनेक्टिविटी: डिजिटल इंडिया ने भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के तेजी से विस्तार में योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, देश भर में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और पिछले दशक में भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है।

- **दूरसंचार, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच:** भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 133+ करोड़ हो गए।
- इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 109.27 करोड़ हो गई।
- वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से कुल इंटरनेट ग्राहक आधार में वर्षवार वृद्धि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	प्रतिशत में वृद्धि
2021–2022	≈ 825 मिलियन	-
2022–2023	≈ 881 मिलियन	6.83%
2023–2024	≈ 954 मिलियन	8.30%.
2024–2025	≈ 969 मिलियन	1.54%.
2025–2026	≈ 1092 मिलियन	12.75%

*स्रोत: टीआरएआई

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं वितरण: किफायती डेटा, सहायक डिजिटल एक्सेस प्वाइंट और इंटरऑपरेबल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने, डिजिटल भुगतान करने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और शासन में भाग लेने में सक्षम बना रहे हैं। डेटा लागत 2014 में 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर 2025-26 में लगभग 8-10 रुपये प्रति जीबी हो गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया है।

- **आधार ने** सुरक्षित और तत्काल डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए एक विश्वसनीय बायोमेट्रिक पहचान मंच बनाया है। 1.44+ बिलियन से अधिक आधार नंबर तैयार किए गए हैं।
- **डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी)** - आधार से जुड़े डीबीटी के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (56 मंत्रालयों की 318 योजनाओं) से नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रान्सफर किए जाते हैं। देश भर में डीबीटी के माध्यम से 52 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं।
- **डिजिलॉकर** नागरिकों को मूल जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म में 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 2,822 ऑनबोर्ड जारीकर्ताओं द्वारा 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।
- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)** नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों के लिए 2,575 सेवाएँ प्रदान करता है।
- **ई-संजीवनी** आपके स्मार्टफोन से सीधे डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने देश भर में 48 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा प्रदान की है।
- **एपीआई सेतु** ने 8,682 से अधिक एपीआई के साथ सरकारी एप्लीकेशनों के बीच सुरक्षित इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम किया है, जिसमें 2,814 से अधिक प्रकाशक और 8,586 उपभोक्ता शामिल हैं, जिससे कुशल डिजिटल सेवा वितरण की सुविधा मिलती है।
- **ई-साइन** ने कानूनी रूप से वैध डिजिटल हस्ताक्षर और अनुमोदन की सुविधा प्रदान की, जिससे कागज रहित और संपर्क रहित वातावरण में सरकारी प्रक्रियाओं, प्रशासनिक कार्यों और व्यावसायिक लेनदेन के निर्बाध निष्पादन को सक्षम किया गया। सभी ई-साइन सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) द्वारा कुल 150.57 करोड़ ई-साइन जारी किए गए।
- **मेरी पहचान (नेशनल सिंगल साइन-ऑन)** ने क्रेडेंशियल्स के एक सेट के माध्यम से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाया, उपयोगकर्ता की सुविधा को बढ़ाया और डिजिटल सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों की 17,018 सेवाओं को एनएसएसओ के साथ एकीकृत किया गया है और मेरी पहचान प्लेटफॉर्म पर 227.87 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए हैं।
- **सामान्य सेवा केंद्र –** सीएससी ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं। मई 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.01 लाख सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 3.91 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्यरत हैं।
- डिजिटल सेवाओं में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) - **भाषिनी** शुरू किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए एक

सार्वजनिक डिजिटल मंच के रूप में की गई है। भाषिणी मंच भारत की विविध आबादी के लिए संचार बाधाओं को दूर करता है।

डिजिटल भुगतान: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने देश भर में डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी है। यूपीआई ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में काफी प्रगति हुई है। यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित आठ से अधिक देशों में लाइव है, जिससे भारत डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक अग्रणी बन गया है।

- यूपीआई 55.49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 731 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।

- भारत के डिजिटल पेमेंट का 85% और दुनिया भर के रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट का लगभग 50% यूपीआई के ज़रिए होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार यूपीआई आंकड़े https://www.npci.org.in/product/ecosystem-statistics/upi पर उपलब्ध हैं।

- डिजिटल भुगतान लेनदेन में खुदरा डिजिटल भुगतान और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) लेनदेन शामिल हैं। 2021 के बाद से डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल संख्या में वर्षवार वृद्धि इस प्रकार है:

कैलेंडर वर्ष	कुल डिजिटल भुगतान		प्रतिशत में वृद्धि	
	वॉल्यूम (करोड़)	मूल्य (लाख करोड़)	वृद्धि की मात्रा	वृद्धि मूल्य
सीवाई-2021	6364.52	1675.24	-	-
सीवाई-2022	10361.04	2004.26	62.79%	19.64%
सीवाई-2023	14966.51	2320.84	44.45%	15.80%
सीवाई-2024	20786.56	2759.53	38.89%	18.90%
सीवाई-2025	26761.90	3143.67	28.75%	13.92%

*स्रोत: आरबीआई

भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग: हमारा आईटी उद्योग निर्यात के विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन में उत्तरोत्तर योगदान दे रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। नैसकॉम के अनुसार, आईटी और आईटीईएस उद्योग ने वित्त वर्ष 25 में 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न करने का अनुमान लगाया है। भारत के 2,100+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और एआई-संचालित भूमिकाओं में लगभग 26 लाख पेशेवरों को रोजगार देते हैं।

डिजिटल उद्यमिता: भारत के टियर- II और टियर- III शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी डोमेन में उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहल इस प्रकार हैं:

- सरकार ने 73 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें से 65 केन्द्र टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं।
- 'जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस)' योजना में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स की खोज, पोषण और विकास के लिए लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। यह योजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में 65 ऊष्मायन केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है

डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना: सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल सेवा वितरण का विस्तार करके, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाओं तक पहुंच को सक्षम करके और नागरिक जागरूकता के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। इसमे शामिल है:

- ग्राम पंचायतों और ग्रामीण संस्थानों के लिए भारतनेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार। जून 2026 तक, देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। जून 2026 के दौरान, 80,472 ग्राम पंचायतों पर भारतनेट प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) चालू थे।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित 4जी सेचुरेशन परियोजना और अन्य मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत, जून 2026 तक देश में 24,812 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।
- सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) 800 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करते हैं, जिससे ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार होता है। मई 2026 तक, देश भर में 5.01 लाख सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 3.91 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर हैं।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। देश भर में कुल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। यह योजना 31.03.2024 को संपन्न हुई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस), 2022-23 के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के 78.4% व्यक्तियों ने संलग्न फाइलों के साथ संदेश भेजने की क्षमता की सूचना दी, जो युवाओं के बीच बेहतर डिजिटल कौशल का संकेत देता है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन/मोबाइल फोन है।
- फ्यूचरस्किल्स प्राइम उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत, अब तक, 34+ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 23+ लाख अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया गया है।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) देश भर में 56 केन्द्रों और 9,000 से अधिक भागीदार संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एसीसी और सीसीसी सहित डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नाइलिट द्वारा 31.92 लाख+ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म: यह प्लेटफॉर्म उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल-आधारित उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक 2.75 लाख+ अभ्यर्थियों ने नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण कराया है।
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने बहुभाषावाद को सक्षम करने वाली स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं।
- सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन सृजित करने और लोगों के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा साइबर जागरूकता - सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रम लागू किया गया है। अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 11.37 लाख+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

******